तत्काल प्रकाशनार्थ

यूपी की डिस्कॉम्स किफायती जनरेटिंग स्टेशन से बिजली खरीदकर हर साल 900 करोड़ रु. की बचत कर सकती हैं: सीईईडब्लू

नई दिल्ली, -- जुलाई, 2020। मेरिट ऑर्डर डिस्पैच (एमओडी) का कठोर अनुपालन उत्तर प्रदेश की डिस्कॉम्स के लिए प्रतिवर्ष 900 करोड़ रु. की बचत कर सकता है। यह बात काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्लू) द्वारा आज जारी एक स्वतंत्र अध्ययन में सामने आई। एमओडी की प्रक्रिया के तहत डिस्कॉम्स सबसे किफायती प्लांट्स से बिजली की खरीद को प्राथमिकता देते हैं। मौजूदा समय में डिस्कॉम्स अनेक समस्याओं के चलते एमओडी से अक्सर विचलित हो जाते हैं, जिनमें कुछ लो-कॉस्ट जनरेटिंग स्टेशंस पर कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना, अकुशल ऑपरेशनल शेड्यूलिंग एवं लचीली भुगतान शर्तों के चलते राज्य के स्वामित्व के जनरेटर डिस्पैच को प्राथमिकता दिया जाना है। उत्तर प्रदेश के डिस्कॉम्स ने वित्तवर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक राजस्व में 4500 करोड़ रु. के राजस्व कमी की बात कही है।

बिजली खरीद का खर्च यूपी डिस्कॉम्स के कुल वार्षिक खर्च का 75 से 85 प्रतिशत है। बिजली खरीद के खर्च को कम करके, खासकर एमओडी का पालन करके राजस्व कमी को कम किया जा सकता है। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) योजना के आंकलन के आधार पर, सीईईडब्लू ने पाया कि उत्तर प्रदेश के डिस्कॉम्स ने पिछले सालों में बेची गई हर यूनिट बिजली पर 80 पैसे से ज्यादा का नुकसान उठाया है।

सीईईडब्लू में रिसर्च फैलो, कार्तिक गणेशन ने कहा, "कोविड-19 महामारी की वजह से उपभोक्ताओं की बिजली की डिमांड और पैसे देने की क्षमता, दोनों प्रभावित हुई है। इसलिए बिजली खरीद की प्रक्रिया में अक्षमताओं को दूर करना अब और ज्यादा जरूरी हो गया है। राजस्व बढ़ाने की विशाल चुनौतियों के चलते डिस्कॉम्स के पास लागत में कटौती करने के अलावा दूसरा उपाय नहीं बचता है। एक महत्वपूर्ण कदम यह होगा कि उन विभिन्न प्लांट्स में कोयले का आवंटन पुनः सुनिश्चित किया जाए, जहां से राज्य बिजली खरीदता है। इससे सुनिश्चित हो सकेगा कि सबसे ज्यादा किफायती प्लांट उतनी बिजली उत्पन्न कर सकेंगे, जितनी तकनीकी दृष्टि से उत्पन्न किया जाना संभव है। राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) एवं यूपी डिस्कॉम्स को एक साथ आकर कोयले की उपलब्धता एवं मूल्यों को तर्कसंगत बनाना होगा।"

सीईईडब्लू के अध्ययन में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि उत्तर प्रदेश के डिस्कॉम्स ने हाल ही में अनुबंधित तीन उत्पादन स्रोतों को स्ट्रेन्डिड फिक्स्ड शुल्क के रूप में वित्तवर्ष 18-19 में 3000 करोड़ रु. खर्च किए, जो उनकी कुल खरीद लागत का लगभग छः प्रतिशत है। यह भुगतान नए जनरेशन के कैपेसिटी एडिशन प्लान के साथ वित्तवर्ष 2023 तक 10,000 करोड़ रु. हो जाएगा। राज्य के डिस्कॉम्स को मौजूदा एस्सेट्स का बेहतर उपयोग करना होगा, पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त बिजली खरीदने पर विचार करना होगा और नई क्षमता को कमीशन या अनुबंध करने से पहले ऐसे अन्य विकल्प तलाशने होंगे।

सीईईडब्लू के प्रोग्राम एसोशिएट, प्रतीक अग्रवाल ने कहा, "राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के डिस्कॉम्स की बकाया राशि उत्पादकों की संपूर्ण बकाया राशि के 15 प्रतिशत के बराबर है। लागत का खुलासा करने में पारदर्शिता आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसके तहत डिस्कॉम्स को बिजली उत्पादकों को भुगतान करने में मदद करने के लिए 90,000 करोड़ रु. की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के रेगुलेटर को सभी लागत एवं नुकसानों की उचित पहचान करनी चाहिए। इसके अलावा डिस्कॉम्स की वित्तीय सेहत राज्य सरकार द्वारा जारी न की गई अतिरिक्त सब्सिडी जारी किए जाने पर भी निर्भर है।"

अध्ययन में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि आपूर्ति की औसत लागत एवं प्राप्त हुए औसत राजस्व के बीच का मौजूदा अंतर कम भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या में अनमीटर्ड कंज़्यूमर और बिलिंग एवं कलेक्शन की कम प्रभावशीलता के कारण हो सकता है।

अध्ययन "कॉस्ट-इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्कॉम ऑपरेशंस इन उत्तर प्रदेश: इंपैक्ट ऑफ उदय, पॉवर पर्चेज़ प्लानिंग एंड डिस्पैच यहां पर देखा जा सकता है।

सीईईडब्लू के बारे में

काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्लू) एशिया का अग्रणी नॉट-फॉर-प्रॉफिट पॉलिसी शोध संस्थान है। यह काउंसिल डेटा, इंटीग्रेटेड विश्लेषण एवं सामरिक आउटरीच का उपयोग कर संसाधनों के उपयोग, पुनः उपयोग एवं दुरुपयोग की व्याख्या व परिवर्तन करता है। सीईईडबल्यू अपने उच्च गुणवत्तापरक शोध की स्वतंत्रता पर गर्व महसूस करता है और निजी व सार्वजनिक संस्थानों के साथ साझेदारी विकसित करते हुए अधिकाधिक लोगों से जुड़ने का प्रयास करता है। 2020 में सीईईडब्लू एक बार फिर '2019 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडैक्स रिपोर्ट' में नौ श्रेणियों में विस्तृत रूप से प्रदर्शित हुआ। काउंसिल दुनिया के सर्वोच्च जलवायु परिवर्तन थिंक टैंक्स में निरंतर स्थान हासिल करता आ रहा है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें ट्विटर @CEEWIndia पर फौलो करें।

Contact: Riddhima Sethi, riddhima.sethi@ceew.in; +91 9902039054
Mihir Shah, mihir.shah@ceew.in